



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1993/भाद्र 29, 1915
No. 557] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1993/BHADRA 29, 1915

नागरिक पूति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1993

का. धा. 704(अ):— केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन अपार एग्री प्रोडक्ट्स मंडी प्रा. लि. दिल्ली द्वारा मान्यता के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड में अग्रिम संविदाओं के बारे में 20 सितम्बर, 1993 से 19

सितम्बर, 1995 (दोनों दिन शामिल हैं) तक दो और वर्षों के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त कम्पनी ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मि. सं. 12/4 आई.टी. 92]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC
DISTRIBUTION
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 1993

S.O. 704(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Apaar Agro Products Mandi Pvt. Ltd., Delhi, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a period of two years from the 20th September, 1993 to 19th September, 1995 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Company shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/4/IT/92]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser